श्री ल० ना० मिश्र : यह सवाल तो एक खास मकान के बारे में था । जहां तक पुराने का ताल्लुक है उनके मकानों को देखा जा रहा है, और उनके बारे में जो कानून हैं उसके जरिए हम नोटिस देते हैं और मकान बनाने के लिए कहते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : यह मकान पुरानी दिल्ली के किस मुहल्ले या बाजार का है, और क्या उस इलाके में और भी ऐसे मकान पाए गए हैं जो कि गिरावट की हालत में हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक खास मकान के बारे में सवाल है । सारे इलाके के बारे में नहीं है ।

श्री काशी राम गुप्त : मैंने यह पूछा कि यह मकान किस मुहल्ले में है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस मुहल्ले में जाना चाहते हैं । आप उस मुहल्ले में मकान न लीजिए ।

मद्य निषेध

+

*480. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बागड़ी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 3 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) इस मामले में राज्य सरकारों से जो सम्मतियां मांगी गई थीं क्या वे भी प्राप्त हो गई हैं ; और

(ग) समिति के निष्कर्षों के आधार पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). वह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है । राज्य सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने से पूर्व क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के विचार भी जान लिए हैं, क्योंकि उन में से कुछ ने सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-निषेध नीति का विरोध किया है । सरकार का अपना मन क्या है ? क्या वह इस मद्य-निषेध नीति पर चलना चाहती है या नहीं ? वह अपनी स्थिति तो स्पष्ट करे ।

श्री हाथी : रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वह स्टेट्स को और सेंट्रल प्राहिबिशन कमेटी के सदस्यों को भेजी गई । अभी उनके मन्तव्य प्राप्त नहीं हुए हैं । हम सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि हम उनके विचार भी जान लें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने खुद निर्णय ले लिया है कि उसकी क्या पालिसी है ।

श्री हाथी : सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि प्राहिबिशन होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में किन स्टेजिज़ से कदम उठाया जाये, उस का फ़ैसला तो स्टेट्स के साथ सलाह मशवरा करके ही किया जा सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केन्द्रीय सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में मद्य-निषेध नीति का पालन किया है, अथवा राज्य सरकारों ने जिन-जिन क्षेत्रों में मद्य-निषेध नीति को अपनाया है, क्या सरकार ने यह जानने का यत्न किया है कि उन क्षेत्रों का क्या अनुभव है ?

श्री हाथी : जी हां, जो रिपोर्ट आई है उसमें हर एक स्टेट को तीन भागों में बांटा गया है : वैट स्टेट्स, ड्राई स्टेट्स और पार्शली वैट और ड्राई स्टेट्स । हर एक स्टेट में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या क्या मुसीबतें हैं, वे सब बातें इस रिपोर्ट में हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य एक्सपीरियंस की बात पूछ रहे हैं, तो वह तो उन्होंने बम्बई का पढ़ा ही होगा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : "बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यं मद्यं तदुच्यते"— शराब अन्दर और अक्ल बाहर ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य उपदेश देंगे या सवाल करेंगे ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं यह बात कह कर सवाल ही कर रहा हूं : जब सरकार को यह बात मालूम है, तो उसको पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने में क्या आपत्ति है ?

श्री हाथी : वह तो हर एक स्टेट में करने की बात है । स्टेट्स के साथ सलाह-मश्वरा करने के बाद निश्चय किया जायेगा ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: In the past some of the State Governments have expressed themselves definitely against prohibition policy. I would like to know whether, in view of the past experience that the Government of India have had and the statements that have been made by some of the State Governments, there is any likelihood of a change of policy in these States.

Shri Hathi: As I said, the report has been sent to the various State Governments, and the matter has to be discussed, but, as I said, the policy of the Government is there, decided.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: They have already made a committed statement that they are not prepared to follow the policy. In view of this, is there any likelihood of any change?

Mr. Speaker: She knows it better.

Shri Koya: We also want to know.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि जहां से प्राहिबिशन को हटा दिया गया है, ख़ास तौर पर कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल सिटी से, वहां पर मज़दूरों की हालत बद से बदतर हो गई है और जहां सब से ऊंची इमारत पर लिखा होता था "आराम हराम है", वहां अब लिखा हुआ है "डीलक्स ह्विस्की" ?

श्री हाथी : दोनों प्रकार के किस्से मालूम हैं—एक वह, जो कि मेम्बर साहब ने बताया है और दूसरा वह भी मालूम है कि जहां प्राहिबिशन इम्प्लीमेंट हुआ है, वहां पर मज़दूरों की स्थिति अच्छी हुई है ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में

शराबबन्दी का कानून लागू हुआ है, वहां पर यह कानून लागू होने से पहले फ़ीकस, पर कैपिटा, शराब की खपत क्या थी और कानून लागू होने के बाद पर कैपिटा खपत क्या है ? अगर उस में अन्तर नहीं हुआ है या अगर वह बढ़ी है, तो उस का क्या कारण है ?

श्री हाथी : ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखी हैं ।

Shri D. C. Sharma: May I know if this report has made any recommendations for the stopping of illicit distillation in the various districts all over India? Have they made any concrete and constructive suggestion with regard to that?

Shri Hathi: The report dealt with this aspect in very great detail and I think I have sent a copy to the hon. Member also.

श्री यशपाल सिंह : क्या यह बात सही है कि अब तक भी पब्लिक सैक्टर में शराब बनाने के कारखाने चल रहे हैं; यदि हां, तो वे कहां कहां चल रहे हैं और कितने हैं ?

श्री हाथी : मेरे पास इस समय इस की सूचना नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन के द्वारा अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब कितनी पकड़ी गई है । क्या राज्यों में भी इस तरह के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं ? क्या शराबबन्दी के सम्बन्ध में केन्द्र के मंत्रियों में कुछ मतभेद है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न प्राहिबिशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में है । माननीय सदस्य को जो सूचना चाहिए, उस के लिए वह नोटिस दें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या इस में सम्बन्ध कैबिनेट में कोई मतभेद है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर सारी कैबिनेट बैठे और पूरे एक महीने की रिसेस में बैठी रहे, तो ये आंकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : सरकार शराबबन्दी का कानून लागू करने की बात करती है, लेकिन विदेशों से हजारों रुपये की शराब मंगाई जा रही है । मंत्रि-मंडल के सदस्यों को जो ड्यूटी-फ्री शराब मिलती है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्रि-मंडल को फ्री मिलती है ? अगर मन्त्रि-मंडल को फ्री मिलती हो, तो मेरे हिस्से भी कुछ आ जाता ।

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that this report is still under the consideration of Government, I would like to know whether the Central Government or the Planning Commission has given any suggestion to any State that they should not take any derogatory step as far as Prohibition is concerned.

Shri Hathi: The matter was discussed in the meeting of the Chief Ministers in 1963 and I think the hon. Member knows about it.

Mr. Speaker: Shrimati Yashoda Reddy.

Shrimati Savitri Nigam: I am asking this question after the report had been submitted . . .

Mr. Speaker: Now, another respectable lady.

Shrimati Yashoda Reddy: Thank you, very much. I would like to know from the hon. Minister upto what percentage of alcohol is the Government of India thinking to permit where beer is allowed in Maharashtra?

Shri Hathi: It is not a question of the Government of India permitting. It is for the State Government. But the Committee has suggested that the

content of alcohol should be decreased gradually.

Shri P. Venkatasubbaiah: Pending the finalisation of the report with consultation of various State Governments, may I invite the attention of the hon. Minister to the fact that there has been a committee by name the Ramamurthi committee which has sat on this prohibition issue and submitted its report? Will this committee's report also be taken into consideration before finalising the conclusions?

Shri Hathi: We will take everything into consideration.

श्री ग्र० प्र० शर्मा : जब प्राहिबिशन एन्क्वायरी कमेटी सारे देश में जांच कर रही थी, उस समय देश के करीब करीब सभी मजदूर संगठनों ने शराब-बन्दी के पक्ष में अपनी राय दी थी। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां जहां मजदूरों के क्षेत्र हैं, वहां शराब-बन्दी से बहुत फ़ायदा हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि कम से कम मजदूर क्षेत्रों में नशाबन्दी पूरे तौर से लागू कर दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सजेस्चिन है।

Shri Jaipal Singh: There had been so many reports of committees and commissions on this delightful subject. May I know whether at any stage the financial implications of prohibition had been given by the committee, what impact it will have on the Fourth Five Year Plan and so forth?

Shri Hathi: The Tek Chand committee has looked into the financial aspects also. It had given various figures about the loss of revenue which the States would have to incur.

Shri Basumatari: In view of the fact that Assam has the largest number of Tribals, may I know whether when these tribals appeared before the Commission, before the Tek Chand Commission, these tribals, who are addicted to drinking, spoke in favour of prohibition?

Shri Hathi: Those details may not be with me.

Shri Hem Barua: In the Assam tribal areas they need liquor for poojas and all that and, according to experts, the people in Assam have to take liquor or else they get de-vitalised because of the cold climate there. May I know whether that aspect of Assam has also been taken into consideration?

Shri Hathi: The Committee has taken that aspect also.

Mr. Speaker: The hon. Member also may be consulted.

Fertilizer production programme

*482. + **Shri Bagri:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri D. C. Sharma:
Shri Yashpal Singh:
Shri Manabendra Shah:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether a group of six American private manufacturers of petrochemicals and fertilisers have formed a consortium to participate in India's fertiliser production programme; and

(b) the terms of the participation proposal and whether the proposal has been approved by Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b). On behalf of an American Consortium, an American firm has submitted a proposal for production and distribution of fertilisers to the extent of 1 million tonnes of nitrogen, by the end of the Fourth Plan period. The firm has been allowed to undertake a feasibility study to be completed by the end of December, 1964. The terms of participation etc. will be known only after the feasibility report is received.